भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2141

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीपीएस अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों के साथ भेदभाव

†2141. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में सीपीएस अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन सीपीएस अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों को पूरे देश में मान्यता प्रदान करने के लिए कोई राजपत्र आधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके राष्ट्रीय महत्व और देश के हजारों समर्पित चिकित्सा पेशेवरों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 35 में भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान जो स्नातक या स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अर्हता प्रदान करता है, जो ऐसी एनएमसी द्वारा बनाई गई सूची में शामिल नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता देने वाला पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले एनएमसी में आवेदन कर सकता है। कुछ राज्यों ने सीपीएस की अर्हताओं को अपने राज्य के कानून के सांविधिक उपबंधों के आधार पर मान्यता दी है।

*****